Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Demand to scrap the Gorkhaland Territorial Administration (GTA) elections in Darjeeling, West Bengal.

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): माननीय सभापति महोदय, दार्जिलिंग में जीटीए के नाम से एक ऑटोनॉमस बॉडी चलती है, मैं उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु आपके सामने रखना चाहूंगा।

हम सब जानते हैं कि दार्जिलिंग को अलग राज्य बनाने की मांग बहुत पुरानी है। इसके साथ ही दो बार सेमी-ऑटोनॉमस बॉडी को लेकर प्रयोग हुए हैं। वर्ष 1988 में दार्जिलिंग-गोरखा हिल काउंसिल बनी और वर्ष 2012 में केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा दार्जिलिंग की लोकल पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से जीटीए बना। वर्ष 2017 में जीटीए का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और जो उसके मेन सिग्नेटरीज थे, उन्होंने भी जीटीए से पूरी तरह त्यागपत्र दे दिए और जीटीए को डिसॉल्व कर दिया।

हुआ यूं कि वर्ष 2017 के बाद दार्जिलिंग पर एक ग्रहण सा लग गया। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार उसको लेकर राजनीति कर रही है। वैसे भी टीएमसी का कभी भी गोरखा के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रहा। वर्ष 2017 के बाद बगैर चुनाव के अभी तक जीटीए किसी नॉन-इलेक्टिड व्यक्ति, कभी किसी ब्योरोक्रैट या उनके किसी पॉलिटिकल मित्र को बैठाकर चलाया जा रहा है। इसकी वजह से क्षेत्र की जनता का बहुत नुकसान हुआ है।

अभी हाल ही में केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की जो एलायेंस पार्टी है, उनके बीच ट्राइपिटाइट-टॉक्स स्टार्ट हुई है कि दार्जिलिंग तराई डूअर्स की जो लंबे समय से चली आ रही मांग है, उसका कोई राजनीतिक समाधान निकाला जाए। उनके बीच यह वार्ता चल रही है, लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री दार्जिलिंग जाती हैं और दोबारा जीटीए चुनाव कराने की बात करती हैं। इससे दार्जिलिंग का माहौल दोबारा खराब हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि जीटीए का चुनाव बिलकुल नहीं होना चाहिए, उसे केन्द्र सरकार पूरी तरह खारिज कर दे, क्योंकि केन्द्र सरकार भी उसमें सिग्नेट्री है। दूसरी बात यह है कि जो स्थायी राजनीतिक समाधान होगा, उससे राष्ट्र का भला होगा, गोरखाओं का भला होगा और उस क्षेत्र में रहने वाली जनता का भी भला होगा। इससे सिक्किम का भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जाने-अंजाने सिक्किम का भी बहुत नुकसान होता रहा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।